

संपादकीय

रुपये की सेहत

आर्थिक मोर्चे पर लगातार कई ऐसी खबरें आई हैं जो राजग सरकार की चिंताएं बढ़ाने वाली हैं। अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों पर कर बढ़ाने, कच्चे तेल के दामों में तेजी, स्विस बैंकों में भारतीयों के काले धन का डेढ़ गुना बढ़ने से मोदी सरकार के माथे पर बल पड़ना स्वाभाविक है। सबसे बड़ी चिंता रुपये की कीमत में लगातार आने वाली गिरावट की है। जिसके चलते रुपया गुरुवार को डॉलर के मुकाबले न्यूनतम स्तर 69 रुपये तक जा पहुंचा। विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय बाजार में जमकर बिकवाली भी इस गिरावट की अहम वजह है। दरअसल, अमेरिका में बढ़ती व्याज दरों ने भी रुपये की चाल बिगाड़ी है। अमेरिकी बॉन्ड्स से होने वाली कमाई बढ़ने से अमेरिकी निवेशक भारतीय बाजार से निवेश निकालकर ले जा रहे हैं। दरअसल जहां रुपये की कीमत में गिरावट के आर्थिक कारण हैं, वहीं राजनीतिक भी। सबसे बड़ी वजह तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का साढ़े तीन साल में उच्चतम स्तर पर होना है। विडंबना यह है कि भारत को कच्चे तेल का बड़ा हिस्सा आयात करना पड़ता है और उसका भी बड़ा भाग डॉलर में आयात किया जाता है। हालांकि, शुक्रवार को रुपये की सेहत कुछ सुधरी है। दरअसल, चीन व अमेरिका के बीच जारी ट्रेड वार से भी आर्थिक स्थितियां प्रतिकूल हुई हैं। भारत की इस युद्ध से प्रभावित है। जवाबी कार्रवाई के तौर पर भारत ने भी कुछ अमेरिकी उत्पादों पर आयात शुल्क बढ़ाया है। आने वाले दिनों में भारत की मुसीबतें और बढ़ सकती हैं क्योंकि अमेरिकी दबाव है कि भारत ईरान से कच्चा तेल न खरीदे। समस्या यह भी है कि भारत ईरान को कच्चे तेल का भुगतान रुपये में करता है। यदि भारत अन्यत्र तेल?खरीदने को बाध्य हुआ तो भुगतान डॉलर में करना पड़ेगा, जिससे रुपये की सेहत पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। वैसे भी भारत ने चाबहार बंदरगाह समेत कई ईरानी परियोजनाओं में निवेश कर रखा है, जिस पर अमेरिकी दबाव से बुरा असर पड़ सकता है। अमेरिकी दबाव से उबरने के लिये भारत को कारगर रणनीति बनानी होगी। हाल ही में भारत व चीन ने मिलकर कुछ देशों से कच्चे तेल की खरीद पर लगे अतिरिक्त आयात कर को घटाकर सफलता पाई थी। ऐसी कोशिश भारत नये सिरे से चीन के साथ मिलकर अमेरिकी चुनौती के मुकाबले के लिये कर सकता है। बहरहाल, रुपये के मूल्य में गिरावट से देश में महंगाई बढ़ने की आशंका भी बढ़ गई है। जिससे हमारे अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन भी दबाव में आ सकते हैं। डॉलर में होने वाला भुगतान महंगा होगा, विदेशों में बच्चों की पढ़ाई व विदेश यात्राएं महंगी हो जायेंगी।

बेबसी की सांझ

संशोधनों के बावजूद सरकार के भरण-पोषण अधिनियम से कितने बुजुर्ग मां-बाप लाभान्वित हो पा रहे हैं, जिनकी संतानें उन्हें जीवन की सांझ में निराश्रय छोड़ गयी हैं, यह प्रश्न अभी तक निरुत्तर है। इसे सिस्टम की खामी कहे या मानवीय रिश्तों में आ रही गिरावट, कि लाचारी की दशा में भी औलाद के भय से बुजुर्ग अपने इस हक का बहुत कम इस्तेमाल कर पा रहे हैं। कुछ अपवाद जरूर हैं जो बाकी लोगों के लिए सनद का काम कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों एक और मैंने न अदालत का दरवाजा खटखटाया है। इस बार यह मां कोई साधारण महिला नहीं, बल्कि मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री तथा पूर्व केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री दिवंगत अर्जुन सिंह की पत्नी सरोज कुमारी हैं। उसने अदालत से गुहार लगाई है कि उन्हें भोपाल स्थित अपने निवास केरवा कोठी में रहने के लिए जगह दिलवाई जाए क्योंकि उसके दोनों बेटे उसकी देखभाल नहीं करते। सरोज कुमारी की उम्र 84 वर्ष है और वह आर्थिक तंगी से दो-चार हो रही है। बुजुर्गों खासकर मांओं के लिए यह स्थिति बड़ी ही कष्टकारी है जब इस उम्र में उन्हें किसी पुख्ता संबल की जरूरत होती है, औलाद उन्हें बेसहारा छोड़ देती है। जिन बच्चों के लिए वह अपना पेट काटती है, खुद गीले में सोकर बच्चों को सूखे में सुलाती है, अंत में उसी मां को उसके बेटे उसके पति के घर से निकाल देते हैं।

ममता तो अब हर जगह छली जाने लगी है। किसी भी मां के लिए यह इतना आसान भी नहीं कि वह इस ममता को दरकिनार कर अपने बेटों के खिलाफ केस करे, वह भी उम्र के इस मोड़ पर जब इनसान की जरूरतें कमतर होती जाती हैं। औलाद का महं, प्यार व देखभाल ही उसे जिंदा रखती है। लेकिन पानी सिर से गुजर जाता होगा जो विवशातवाश बुढ़ापे में भी उन्हें यही किकल्प दिखता होगा। विसंति देखिए कि उन्हें चोटील कौन कर रहा है? अपना ही खून, उसके अपने लख्ते जिगर, जिनके जन्म पर उन्होंने लाख-लाख बलेयां ली थीं। ममतें भी मांगी थीं। कहीं बेटा मां को पीटता है, कहीं किसी बुजुर्ग मां को घर से बाहर निकाल दिया जाता है, कहीं मां के बैक खाते से सारी जमा पूंजी निकाल ली जाती है तो कहीं मां के मकान पर कब्जा करके उसे गुरुद्वारे में छोड़ दिया जाता है। देश में कितने ही केस ऐसे हैं जहां बुजुर्गों की खातिर अदालतों ने बेटों को नसीहतें दी हैं ताकि वे शर्मसार हो।

ओशो

कामना

व्यक्ति जो स्वस्थ, निर्भर, निर्बांझ, ताजा, युवा, कुंआरा अनुभव करता है, वही समझ पाएगा कि संतोष क्या है। संतोष का अर्थ है- जो कुछ है सुंदर है; यह अनुभूति कि जो कुछ भी है श्रेष्ठतम है, इससे बेहतर संभव नहीं। एक गहन स्वीकार की अनुभूति है संतोष ; संपूर्ण अस्तित्व जैसा है उस के प्रति ‘‘ हां ’’ कहने की अनुभूति है संतोष। साधारणतया मन कहता है, ‘‘ कुछ भी ठीक नहीं है। ’’ साधारणतया मन खोजता ही रहता है शिकायतें- ‘‘ यह गलत है, वह गलत है । ’ साधारणतया मन इनकार करता है- वह ‘‘ न ’’ कहने वाला होता है, वह ‘‘ नहीं ’’ सरलता से कह देता है। मन के लिए ‘‘ हां ’’ कहना बड़ा कठिन है, क्योंकि जब तुम ‘‘ हां ’’ करने हो, तो मन ठहर जाता है; तब मन की कोई जरू रत नहीं होती। क्या तुमने ध्यान दिया है इस बात पर? जब तुम ‘‘ नहीं ’’ कहते हो, तो मन आगे और आगे सोच सकता है; क्योंकि ‘‘ नहीं ’’ पर अंत नहीं होता। नहीं के आगे कोई अंत- विराम नहीं है; वह तो एक शुरु आत है।। ‘‘ नहीं ’’ एक शुरु आत है; ‘‘ हां ’’ अंत है। जब तुम ‘‘ हां ’’ कहते हो, तो मन ठहर जाता है; और मन का वह ठहरना ही संतोष है। संतोष कोई सांत्वना नहीं है-यह स्मरण रहे। मैंने बहुत से लोग देखे हैं, जो सोचते हैं कि वे संतुष्ट हैं, क्योंकि वे तस्ल्ली दे रहे हैं स्वयं को। सांत्वना एक खोटा सिक्का है। जब तुम सांत्वना देते हो स्वयं को, तो तुम संतुष्ट नहीं होते। वस्तुत- भीतर बहुत गहरा असंतोष होता है। लेकिन यह समझ कर कि असंतोष चिंता निर्मित करता है, यह समझ कर कि असंतोष परेशानी खड़ी करता है, यह समझ कर कि असंतोष से कुछ हल तो होता नहीं-बौद्धिक रूप से तुमने समझा-बुझा लिया होता है अपने को कि ‘‘ यह कोई ढंग नहीं है। ’’ तो तुमने एक झूठा संतोष ओढ़ लिया होता हैलेकिन तुम आकांक्षा करते हो। अन्याथा यह आकांक्षा न करने की बात कहां से आती? तुम कामना करते हो, तुम आकांक्षा करते हो, लेकिन तुमने जान लिया है कि करीब-करीब असंभव ही है पहुंच पाना: तो तुम चालाकी करते हो, तुम होशियारी करते हो। तुम स्वयं से कहते हो, ‘‘ असंभव है पहुंच पाना। ’’ भीतर तुम जानते हो-असंभव है पहुंच पाना: लेकिन तुम हारना नहीं चाहते, तुम नपुंसक नहीं अनुभव करना चाहते, तुम दीन-हीन नहीं अनुभव करना चाहते, तो तुम कहते हो, ‘‘ मैं चाहता ही नहीं। ’’ तुमने सुनी होगी कि लोमड़ी के अंगूर खट्टे होने वाली कहानी है। कुछ वैसा ही है।

संपादकीय

हिन्दी के पिछड़ेपन का दोषी कौन?

“ दुखद है कि हिन्दी अंतरिक्ष में पहुंच गई, विश्व भाषा बन गई, संयुक्त राष्ट्र में बोली गई लेकिन अपने यहां उसे शिक्षा के माध्यम का दर्जा नहीं मिला। वह संसद और संविधान में प्रामाणिक दस्तावेज की भाषा नहीं बनी, सरकारी और निजी या भारतीय मूल के बहुराष्ट्रीय संस्थानों में उच्च पदों के रोजगार की भाषा नहीं हुई। इसके लिए कौन जिम्मेदार है- जनता या शासक और प्रशासक? इस प्रश्न के उत्तर में ही हिन्दी के विकास और पिछड़ेपन का समाधान छिपा है

“

“

गिरिश्वर मिश्र

काल एक बड़ा अनोखा और उपयोगी प्रत्यय है पर उसे अपनाने के साथ ही जवाबदेही भी आती है क्योंकि काल के विस्तृत आयाम में हम करते क्या हैं वही खास होता है। तरतीब से जीवन का अर्थ बैठाने के लिए हम सब अपने अनुभवों को भूत, वर्तमान और भविष्य के खांचों में व्यवस्थित करते रहते हैं। पर स्वयं में हर अनुभव अखंड होता है, और काल से परे भी। इसलिए इन काल खंडों के अंतर्गत शामिल होने वाले अनुभवों के बीच आवाजाही भी बनी रहती है। काल के मूल में हमारे अनुभव में आने वाला परिवर्तन ही मुख्य होता है क्योंकि हमारा अनुभव क्षण-क्षण बदलाव से ही उकेरा जाता है। एक अर्थ में स्मृतियों के सहारे पहले हुए अनुभवों का पुनर्जीवन करते रहते हैं। स्मृति में संचित अनुभवों को अपने दर्शन से हम भिन्न-भिन्न प्रयोजनों के लिए उपयोग करते हैं। तात्कालिक स्मृति बड़ी सीमित क्षमता की होती है। इसलिए उसका भार कम करने के लिए हम समग्र अनुभव को कुछ खानों में रख देते हैं। अनुभवकर्ता और उसकी स्मृति व्यवस्था को भी कुछ विश्राम दे देते हैं, और जरूरत पड़ने पर संचित स्मृति को बाहर बुला लिया करते हैं। सूक्ति काल हमारे अनुभव के उपयोग से जुड़ा होता है, इसलिए उसके साथ अवसर कोई न कोई विशेषण जुड़ जाता है। हम सभी सुकाल, अकाल, दुष्काल, अतिकाल, महाकाल और आपात

प्री. मणीन्द्र ठाकुर
संचार और तकनीकी के इस युग में भी बिहार सरकार विद्यालयों तक पाठ्यपुस्तकों को पहुंचाने के लिए संघर्ष कर रही है। पहली व्यवस्था के अनुसार बच्चों को किताबें दी जाती थीं। लेकिन पिछली बार किताबें उन्हें तब नसीब हुईं जब साल लगभग बीत गया। उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार इस वर्ष किताबें समय पर दी जानी थीं। अब फैसला यह लिया गया कि बच्चों के खातों में सीधे पैसे भेज दिए जाएं और बाजार में पुस्तकें उपलब्ध करा दी जाएं। यह प्रक्रिया इतना जटिल है कि समय पर पुस्तकों का उपलब्ध होना और भी मुश्किल सा लगता है। अगले तीन-चार महीने में भी इसके सही होने की उम्मीद कम ही है। आश्रय की बात यह है कि बाकी कई राज्यों में पुस्तकों को छात्रों तक पहुंचने की वही पुरानी प्रक्रिया है, और सफल भी है। फिर बिहार में ही ऐसी अव्यवस्था क्यों हो जाती है? बिहार सरकार पर आप कितना भी आरोप लगा लें यह तो नहीं ही कहा जा सकता है कि शिक्षा विस्तार में उसकी रु चि नहीं है। पिछले कुछ सालों में जिस तरह से साइकिल और ड्रेस आदि बांट कर सरकार ने छात्रों और अभिवावकों में शिक्षा के प्रति उत्साह पैदा किया है, काफी सराहनीय है। लेकिन इस प्रक्रिया को चलाते रहने के लिए सरकार में एक तरह की रचनात्मक ऊर्जा भी चाहिए। शायद अब इसकी कमी हो रही है। ऐसा लगता है कि सरकार की नौकरशाही में कल्पना शक्ति क्षीण हो गई है। प्रशासनिक नेतृत्व में प्रयोग से वे कतराते हैं। पुस्तक

ओं, अजय तिवारी
हिन्दी की दुर्दशा के लिए अक्सर हिन्दी भाषी जनता को दोषी ठहराया जाता है। हिन्दी भाषी प्रदेशों में व्यापक अशिक्षा है; हिन्दी में प्रकृति-विज्ञान तो दूर, समाज विज्ञान के लिए भी अच्छी पुस्तकें नहीं हैं; रूढ़िवाद, जातिवाद और सांप्रदायिकता का सबसे बड़ा गढ़ हिन्दी-प्रदेश है; हिन्दी-दंभ के कारण दूसरे भाषायी क्षेत्र डरते हैं कि उनका विकास रु क जाएगा, आदि-आदि। इस तरह की बातें अक्सर सुनी जाती हैं। जरा रु ककर विचार कीजिए, इन बातों की जिम्मेदारी किसी समुदाय की होती है, या उसका नेतृत्व करने वाली और उस पर शासन करने वाली (राजनीतिक और आर्थिक) शक्तियों की? नीतियां कौन बनाता है, साधन कौन मुहैया करता है?बेशक, हिन्दी का बाजार इतना बड़ा है कि उसकी उपेक्षा का साहस बड़े उद्योगपति भी नहीं कर सकते। जिन संस्थाओं ने सबसे लोकप्रिय पत्रिकाएं एक समय बंद कर दी थीं, उन्होंने दो दशक बीतते-बीतते ‘‘हम बाजार को सरल करके बताते हैं, हम हिन्दी हैं’’ का नारा लगाते हुए वित्त और व्यापार के पत्र हिन्दी में निकाले। हिन्दी भाषी मध्य वर्ग को बाजार से जोड़ना था तो संचार-माध्यमों में हिन्दी की उपेक्षा नहीं की जा सकती थी। 1970 के बाद प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर निजी स्कूलों का विस्तार हुआ, 1980 के बाद उच्च एवं तकनीकी शिक्षा में निजी संस्थाओं का विस्तार हुआ; उसी के साथ शिक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी अधिकाधिक अपदस्थ हुई। जिस मध्य वर्ग को हिन्दी के जरिए सद्गु-बाजार में लाने का उपाय किया जा रहा है, वह अपने बच्चों को अपनी तरह हिन्दी वाला नहीं बनाए रखना चाहता। कारण साफ हैं। प्रेमचंद ने ‘‘रंगभूमि’’ में लिखा था कि अंग्रेजी पढ़कर अफसर बनेगा, उर्दू पढ़कर चपरसी। आज उर्दू वाली स्थिति हिन्दी की है। योग्यता के बाजार में अंग्रेजी की कीमत ज्यादा है। हिन्दी, उर्दू, संस्कृत के लोगों को गिनी-चुनी नौकरियां मिलती हैं। अधिकतर निचले स्तर की। बेहतर भविष्य की आशा हिन्दी से नहीं, अंग्रेजी से जुड़ती है। मध्य वर्ग को भली-भाति अनुभव है कि स्कूलों में हिन्दी बोलने पर ‘‘पनिशमेंट’’ मिलती है। इस ‘‘पनिशमेंट’’ से बचाने के लिए वह घर पर ट्यूशन का बंदोबस्त भी करता है। मुश्किल यह है कि सरकारी विद्यालयों की स्थिति इतनी खस्ता है कि विद्यार्थी वहां शिक्षा कम पाते हैं, कुसरकार ज्यादा। मध्य वर्ग ही नहीं, उसके नीचे किसान, मजदूर, चपरसी, घरों में काम करने वाली बाइयां भी अपने बच्चों को भरसक अंग्रेजी-माध्यम स्कूलों

में लिखा था कि अंग्रेजी पढ़कर अफसर बनेगा, उर्दू पढ़कर चपरसी। आज उर्दू वाली स्थिति हिन्दी की है। योग्यता के बाजार में अंग्रेजी की कीमत ज्यादा है। हिन्दी, उर्दू, संस्कृत के लोगों को गिनी-चुनी नौकरियां मिलती हैं। अधिकतर निचले स्तर की। बेहतर भविष्य की आशा हिन्दी से नहीं, अंग्रेजी से जुड़ती है। मध्य वर्ग को भली-भाति अनुभव है कि स्कूलों में हिन्दी बोलने पर ‘‘पनिशमेंट’’ मिलती है। इस ‘‘पनिशमेंट’’ से बचाने के लिए वह घर पर ट्यूशन का बंदोबस्त भी करता है। मुश्किल यह है कि सरकारी विद्यालयों की स्थिति इतनी खस्ता है कि विद्यार्थी वहां शिक्षा कम पाते हैं, कुसरकार ज्यादा। मध्य वर्ग ही नहीं, उसके नीचे किसान, मजदूर, चपरसी, घरों में काम करने वाली बाइयां भी अपने बच्चों को भरसक अंग्रेजी-माध्यम स्कूलों

में पढ़ाने का प्रयत्न करती हैं। नौकरियों में निजी शिक्षा-संस्थाओं के अलावा इन विद्यालयों से पढ़कर निकले विद्यार्थियों को बेहतर अवसर मिलते हैं। इनके मुकाबले सर्वोदय विद्यालय, नगर पालिका विद्यालय, राज्यों के नियतधर्मे चलने वाले विद्यालयों से पढ़कर निकले विद्यार्थी किस स्थिति में रहते हैं? इसका कोई सर्वेक्षण नहीं होता वरना तस्वीर साफ हो जाए। यही स्थिति हिन्दी के अलावा अन्य भारतीय भाषाओं की है। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए तमिल, पंजाबी, उड़िया के बजाय अंग्रेजी की वरीयता स्पष्ट है। संक्षेप में, शिक्षा के माध्यम और रोजगार के साधन

“

के बीच सीधा रिश्ता होता है। यह बात माता-पिता भी समझने लगे हैं, लेकिन बाजार इसे बहुत अच्छी तरह समझता है। नगरों में नौकरीपेशा परिवारों की कमाई का मोटा हिस्सा मकान के किराये और बच्चों की फीस में निकलता है। फिर, छोटे बच्चों की ट्यूशन और बड़े बच्चों की कोचिंग में मां-बाप कमाल होते जाते हैं, और बाजार मालामाल। स्थिति दिनोदिन भयावह होती जा रही है। सबसे बड़ा कारण है अवसरों का घटते जाना, प्रतियोगिता का बढ़ते जाना और मातृ भाषा का शिक्षा के माध्यम से अपदस्थ होते जाना। शिक्षा-सुधार के नाम पर ‘‘नई’’ शिक्षा नीति आती है, और विद्यार्थियों को पहले से अधिक परजीवी बना देती है। गांधी जी समझते थे कि आजाद भारत में अक्षर-ज्ञान और व्यावहारिक-हुनर का संतुलन शिक्षा नीति का आधार होगा। यह परिप्रेक्ष्य आज तक किसी भी शासन का नहीं बन सका।

प्रसंगवश

एक बहाना है काल

काल जैसे प्रयोगों से परिचित हैं। काल स्वयं में खाली है, अवकाश है, और उसे किस अनुभव से भरा जा रहा है, वह महत्वपूर्ण होता है। आजकल तैतालिस वर्ष पहले घटित हुए ‘‘आपातकाल’’ को स्मरण में ला कर उसकी अनेक व्याख्याएं अपने-अपने प्रयोजन के अनुसार प्रस्तुत की जा रही हैं।

आज चारों ओर काल का अकाल या दुर्भिक्ष पड़ा हुआ है। पैसे दे कर भी उसे खरीदा नहीं जा सकता। समय अमूल्य है, और सबसे निरपेक्ष। उस पर किसी का अधिकार नहीं है। काल सबको दौड़ा रहा है। काम और विश्राम, दोनों के लिए समय कम पड़ता जा रहा है, लगता है एक जिंदगी नाकाफी है। समय की कैद से राहत कैसे मिले

व्यक्तिगत जीवन में काल आज बड़ा कीमती हो गया है। बाजार की वस्तु का रूप ले रहा है। माननीय लोगों से मिलने के लिए टाइम मिलना सौभाग्य होता है। अभी दिल्ली में अद्भुत नजारा था। राज्यपाल से मिलने के लिए उन्हीं के मुख्यमंत्री को समय लेना पड़ता है, और उसके लिए कई दिनों का आंदोलन होता है। अत्यंत व्यस्तता के चलते मंत्री और अधिकारियों से मिलना भी दूमर है। ऊपर से समय

का टोटा पड़ा है। आज चारों ओर काल का अकाल या दुर्भिक्ष पड़ा हुआ है। पैसे दे कर भी उसे खरीदा नहीं जा सकता। समय अमूल्य है, और सबसे निरपेक्ष। उस पर किसी का अधिकार नहीं है। काल सबको दौड़ा रहा है। काम और विश्राम, दोनों के लिए समय कम पड़ता जा रहा है, लगता है एक

जिंदगी नाकाफी है। समय की कैद से राहत कैसे मिले? यह आज यक्ष प्रश्न हो गया है। समय का तनाव पिछले चार-पांच दशकों में खूब बढ़ा है। यह तब है जब विभिन्न तकनीकी उपकरणों के चलते काम के घंटे भी कम हुए हैं पर साथ में सबकी व्यस्तता भी खूब बढ़ी है। यह अलग बात है कि उपलब्ध समय और हमारे द्वारा किए जाने वाले समय का अनुमान इन दोनों में बड़ा अंतर होता है।

बीच समय में

स्कूली किताबें तक नहीं बिहार में

और कपड़ों के लिये पैसे खाते में भेजने का निर्णय इसी स्वभाव को दर्शाता है। छापने के लिए कागज मुहैया कराने से लेकर पुस्तकों के वितरण तक में अफसरशाही के अलग-अलग सौपान की सहभागिता के जरूरत है, जिसका बिहार में अभाव है। पैसे के रहते यदि प्रक्रिया में विलंब हो तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? लगता है कि उच्च न्यायालय

पहले की तुलना में छात्रों की संख्या बहुत बढ़ गई है और बिहार के लिए उसे संभालना आसान नहीं है। लेकिन यह भी सच है कि इस पूरी व्यवस्था को केवल शिक्षा मित्रों के भररोसे संभालना भी संभव नहीं है। देख कर दु:ख होता है कि जिन विद्यालयों के सहारे बिहार ने बड़ा शिक्षित वर्ग तैयार किया था, अब बदहाली हैं। विद्यालयों को पुनः प्रतिष्ठित करने के बदले बिहार सरकार शिक्षा मित्रों के सहारे बच्चों का भविष्य संवारने का सपना देखती है

को ही यह भी आदेश करना होगा कि मूद्रणऔर वितरण का काम स्वयं सरकार करे क्योंकि नई व्यवस्था से तो पुस्तकों के पहुंचने की संभावना और भी कम हो जाएगी। एक अनुमान के अनुसार केवल तीस प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या के पास कोई बैंक खाता है। बच्चों का बैंक खाता केवल अपने अभिभाक्ता के साथ ही खुल सकता है। बैंकों में ऐसे ही कम भीड नहीं होती है। और खाते में यदि थथेष्ट पैसे नहीं हो तो फिर जितना पैसा उन्हें मिलेगा उससे ज्यादा फाइन देना पड़ेगा। ज्ञातव्य है कि उन्हीं पैसों

का विस्तार करना है, तो सरकार को अपने अफसरशाही को जड़ता से निकाल कर उत्तरदायी बनाना पड़ेगा। संभावना यह भी है कि इस नई ठेकेदारी व्यवस्था में कुछ ऊपरी आमदनी की व्यवस्था हो, इसलिए इसमें उनकी रु चि ज्यादा है, ऐसा कहना है बहुत से लोगों का। मुझे इसमें तय नहीं लगता है, लेकिन यह तो जरूर है कि एक जिम्मेदार नौकरशाही के भररोसे ही शिक्षा में सुधार की उम्मीद की जा सकती है। शरिसवपाही में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मंच पर

क्रांति समय

बिड़ला-अंबानी रिपोर्ट को आधार बनाकर पिछले शासन ने जो नीति-परिवर्तन किया था, उसने हुनर के नाम पर उद्योगों के लिए ‘‘मानव-संसाधन’’ जुटाने की शुरु आत की है। नये शासक पिछली सता के प्रत्येक कार्य में दोष देखते हैं, लेकिन इस रिपोर्ट के आधार पर चालू पपाली को हटाने की जगह उसे मजबूत कर रहे हैं। इतिहास में कुछ शासकों का महत्त्व घटाकर और दूसरे शासकों का महत्त्व बढ़ाकर राजनीतिक लक्ष्य साधे जा सकते हैं, मौलिक परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। ‘‘मानव-संसाधन’’ उत्पन्न करने वाली शिक्षा पपाली ने सबसे नुकसानदायक कार्य यह किया है कि उसने शिक्षा से ज्ञान को बहिष्कृत करके सूचना को प्रतिष्ठित किया है। विश्व की प्रभुत्वशाली सत्ताएं आज के युग को ‘‘सूचना का युग’’ कहती हैं। सूचना असम्बद्ध तयों का संकलन है, ज्ञान संबद्ध तयों का विवेक। ज्ञान के लिए भाषा का उतना ही महत्त्व है, जितना तय का। सूचना के लिए भाषा गौण स्थान रखती है। इस नजरिए दूर परिणाम भाषा-विशेषण पर भी पड़ा है। सूचना-केंद्रित अध्ययन कक्षाओं से अधिक कोचिंग-सेंटर के अनुकूल है। यह धंधा जितना फूला-फला है, उससे स्कूलों की शिक्षण-विधि पर प्रश्न चिह्न लग जाता है। दूसरी तरफ, राष्ट्रीय शैक्षणिक एवं अनुसंधान परिषद ने हिन्दी-पाठ्यक्रम से व्याकरण और इतिहास को बाहर कर दिया है। ऐसे में विद्यार्थी जो ‘भाषा’ सीखेगा, वह कैसी होगी? कहने की जरूरत नहीं है।यही विद्यार्थी उच्च शिक्षा में पहुंच कर ‘‘मानव-संसाधन’’ के रूप में विकास करेगा। भाषा और तर्क संगत ज्ञान का आपस में संबंध है। इन दोनों से यथाशक्ति दूर किया हुआ विद्यार्थी अपनी जानकारियों के अंबार से दबा और संतुष्ट, तकनीकी हुनर से धनार्जन में संलग्न, भाषा और सामाजिक चिंता के सवालों से उदासीन, प्रतिरोध और विद्रोह की चेतना से बेगाना, हर स्थिति के अनुसार ढल जाने के योग्य, आज उत्तर-आधुनिक या भूमबलीय समय के लिए उपयुक्त प्रणी है।

भाषा का सवाल एक व्यापक सामाजिक-ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से जुड़ा हुआ है। मातृ भाषाओं के विकास का सवाल सामाजिक संवेदनशीलता और परिवर्तन का मुख्य साधन है। निजी शिक्षा का फैलता बाजार इस लक्ष्य को इतने सधे तरीके से पूरा करता है कि लोगों को लगता है, हिन्दी के पिछड़ेपन का कारण हिन्दीभाषी लोग ही हैं। दु:खद यह भी है कि हिन्दी अंतरिक्ष में पहुंच गई, विश्व भाषा बन गई, संयुक्त राष्ट्र में बोली गई लेकिन अपने यहां उसे शिक्षा के माध्यम का दर्जा नहीं मिला। वह संसद और संविधान में प्रामाणिक दस्तावेज की भाषा नहीं बनी, सरकारी और निजी या भारतीय मूल के बहुराष्ट्रीय संस्थानों में उच्च पदों के रोजगार की भाषा नहीं हुई। इसके लिए कौन जिम्मेदार है-जनता या शासक और प्रशासक? इस प्रश्न के उत्तर में ही हिन्दी के विकास और पिछड़ेपन का समाधान छिपा है।

ज्यादा समय अवकाश का रहता है पर हम उसका अनुमान घटा कर करते हैं। ज्यादा खाली समय होने पर भी अवकाश की संतुष्टि या तृप्ति नहीं होती है। लोग छुट्टी लेने के कोई अवसर नहीं गंवाते हैं। लोकतंत्र में इतने प्रकार की छुट्टियों के प्रावधान हैं कि उनका नियम से पालन करें तो वर्ष छोटा पड़ जाए। अवकाश भी निष्क्रिय और सक्रिय हो सकता है। अवकाश का जो समय बढ़ा वह टेलीविजन के महा देव को समर्पित हो गया। टीवी देखना निष्क्रिय अवकाश होता है। हमारे सामाजिक काम, जिनमें सक्रिय अवकाश का सुख मिलता था, घटता जा रहा है। काल के अंध पर सवारी कैसे करें यह सीखना जरूरी है।काल की चंचा काल-चेतना का उल्लेख किए बिना अधूरी ही रहेगी। हम इतिहास प्रिय हैं। उसे संग्रहालयों में संजोते और सजाते हैं। मनुष्य अपने अंत का सत्य जान कर काल से परे जाने का उपाय करता है। हम सिर्फ इतिहास-चालित नहीं हैं। न मौजूदा परिस्थितियों और आंतरिक दशाओं पर ही पूर्णतः निर्भर करते हैं। वे काम करती हैं, और हमारी गति को प्रभावित भी करती हैं। पर मनुष्य कल्पनाशील है। नवाचार और आविष्कार पर बल देता है। इतिहास धक्का देने वाला कोई बल या फोर्स नहीं है। ज्यादा से ज्यादा वह एक संसाधन है। उत्तरजीवित और पुनरुत्थान जैसे जीवन विषयक प्रश्न भविष्योन्मुख हैं। हमारी चेतना भविष्योन्मुख है, और जीवन का सिरा भविष्य की ओर ही खुलता है।

मुख्यमंत्री को उपस्थित पाकर में अपने आपको यह कहने से रोक नहीं पाया था कि बिहार की जनता के विकास का रास्ता शिक्षा से होकर ही है। यही उनकी उम्मीद है। आर्थिक विकास का कोई और मॉडल तो हमें सफल होता दिखाता नहीं है। लेकिन बिहार जिस ज्ञान परंपरा का उद्गम स्थल रहा है उसे स्थापित करने से शायद हम आर्थिक विकास भी कर पाएं। हमें सोचना होगा कि आखिर, दिल्ली और कोटा जैसी जगहों पर ज्यादातर शिक्षक भी बिहारी हैं और छात्र भी बिहारी हैं, फिर उन्हें बिहार से बाहर क्यों जाना पड़ता है। बिहार के महुआल में ऐसा क्या है कि हमारी सारी शिक्षा संस्थाएं एक-एक कर ध्वस्त हो रही हैं। यहां तक कि आइआइटी और केंद्रीय विविद्यालय भी आखिरी सोपान पर खड़े हैं। मुख्यमंत्री महोदय ने अपने भाषण में मेरा जबाब देने के तर्ज पर प्राथमिक शिक्षा में किय गए अपने कामों का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया। लेकिन यदि आप उनके उपलब्धियों की समीक्षा करें तो सापेक्ष तौर पर भले ही बड़ी सफलताएं हो सकती हैं अपने आप में उसका कोई खस मतलब नहीं हो सकता है। पहले की तुलना में छात्रों की संख्या बहुत बढ़ गई है, और राज्य के लिए उसे संभालना आसान नहीं है। लेकिन यह भी सच है कि इस पूरी व्यवस्था को केवल शिक्षा मित्रों के भररोसे संभालना भी संभव नहीं है। यह देख कर दु:ख और आश्चय होता है कि जिन विद्यालयों के सहारे बिहार ने एक बड़ा शिक्षित वर्ग तैयार किया था, अब सब बदहाली में फंसे हुए हैं। इस विद्यालयों को पुनः प्रतिष्ठित करने के बदले यदि बिहार सरकार

साप्ताहिक समीक्षा : सेंसेक्स 266 अंक, निफ्टी 107 अंक फिसला



मुंबई। वैश्विक स्तर पर बीते सप्ताह अमेरिका और चीन के बीच जारी टैरिफ वार में कई अन्य देशों के शामिल होने से बने दबाव का असर घरेलू बाजार भी दिखा जहाँ बीएसई का 30 शेयरों पर आधारीक संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 266 अंक और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी 107 अंक गिर गया। समीक्षाधीन अवधि में बीएसई का सेंसेक्स 0.75 फीसदी अर्थात् 266.12 अंक गिरकर 35423.48 अंक पर रहा। इस दौरान एनएसई का निफ्टी 107.55 अंक अर्थात् 0.99 प्रतिशत गिरकर 10714.30 प्रतिशत पर रहा। दिग्गज कंपनियों की तुलना में छोटी और मझौली कंपनियों में अधिक बिकवाली हुई जिससे बीएसई का मिडकैप 2.45 प्रतिशत गिरकर 15450.90 अंक पर आ गया।

सोमवार को बीएसई का सेंसेक्स 219.25 अंक गिरकर 35470.35 अंक पर रहा। इस दिन निफ्टी 59.40 अंक टूटकर 10762.45 अंक पर रहा। इसके बाद मंगलवार को सेंसेक्स 19.69 अंक और निफ्टी 6.70 अंक सुधरकर बंद हुआ। बुधवार को सेंसेक्स में 272.93 अंक की तेज गिरावट हुई और यह 35217.11 अंक पर आ गया। निफ्टी भी इस दिन 97.75 अंक फिसलकर 10671.40 अंक पर आ गया।

गुरुवार को भारी उथल पुथल भरे कारोबार के बीच सेंसेक्स 179.47 अंक गिरकर गया और यह 35037.64 अंक पर रहा। निफ्टी भी 82.30 अंक गिरकर 10589.10 अंक पर रहा। हालांकि दो दिनों की गिरावट के बाद शुक्रवार को वैश्विक स्तर से मिले सकारात्मक संकेतों के साथ ही घरेलू स्तर पर लिवाली के बल पर सेंसेक्स 385.84 अंक चढ़कर 35423.48 अंक पर और निफ्टी 125.20 अंक उछलकर 10714.30 अंक पर रहा।

समीक्षाधीन अवधि में आईटी समूह की कंपनी इंफोसिस में सबसे अधिक 4.84 प्रतिशत की तेजी रही। टीसीएस 1.95 प्रतिशत, विप्रो 0.95 प्रतिशत, वेदांता 1.71 प्रतिशत, हिन्दुस्तान यूनिफाइड 2.13 प्रतिशत, एयरटेल 1.71 प्रतिशत और अदानी पोर्ट्स 1.64 प्रतिशत की बढ़त में रहे। सेंसेक्स में गिरावट में रहने वाली कंपनियों में टाटा मोटर्स 12.61 फीसदी के साथ सबसे अधिक नुकसान उठाने वाली कंपनी रही। इस दौरान महिंद्रा 1.25 प्रतिशत, मासुति सुजुकी 0.77 प्रतिशत, हीरो मोटोकॉर्प 4.62 प्रतिशत और बजाज ऑटो 1.69 प्रतिशत की गिरावट में रहे।

कमजोर वैश्विक संकेतों से बीते सप्ताह सोना में गिरावट जारी

नयी दिल्ली। वैश्विक बाजारों में कमजोरी के संकेत और स्थानीय आभूषण विक्रेताओं की मांग में गिरावट आने के कारण दिल्ली के सराफा बाजार में सोने में लगातार तीसरे सप्ताह गिरावट का रुख रहा और इसकी कीमत हानि के साथ 31,420 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई। औद्योगिक इकाइयों और सिक्का निर्माताओं के कमजोर उठाव के कारण चांदी की कीमत भी 400 रुपये की हानि के साथ 41,000 रुपये के स्तर से नीचे 40,600 रुपये प्रति किग्रा पर बंद हुई। बाजार सूत्रों ने कहा कि विदेशों में कमजोरी के रुख के अलावा अमेरिकी व्याज दर में वृद्धि होने की संभावनाओं के बीच हाजिर बाजार में स्थानीय आभूषण विक्रेताओं और फुटकर कारोबारियों की मांग में गिरावट आने के कारण मुख्यतः सोने की कीमतों पर दबाव रहा। वैश्विक स्तर पर न्यूयॉर्क में सोना सप्ताहांत में हानि दर्शाता करीब छह माह के निम्न स्तर 1,252.40 डॉलर प्रति औंस और चांदी हानि के साथ 16.09 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुई। राष्ट्रीय राजधानी में कुछ लिवाली समर्थन के कारण 99.9 प्रतिशत और 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की क्रमशः 31,650 रुपये और 31,500 रुपये प्रति 10 ग्राम पर मजबूत शुरुआत हुई। बाद में इसे प्रतिरोध का सामना करना पड़ा और सप्ताहांत में यह 180 - 180 रुपये की हानि दर्शाती क्रमशः 31,420 रुपये और 31,270 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई। हालांकि, सीमित सौदों के बीच सीमित दायरे में घट बढ़ के बाद गिन्नी की कीमत सप्ताहांत में 24,800 रुपये प्रति आठ ग्राम के पूर्व सप्ताहांत के स्तर पर ही बंद हुई। लिवाली और बिकवाली के बीच उतार चढ़ाव भरे कारोबार में चांदी तैयार की कीमत भी सप्ताहांत में 400 रुपये की गिरावट के साथ 40,600 रुपये प्रति किग्रा पर बंद हुई जबकि चांदी साप्ताहिक डिलिवरी के दाम 570 रुपये की हानि के साथ 39,225 रुपये प्रति किग्रा पर बंद हुई। चांदी सिक्कों की कीमत भी सप्ताहांत में 1,000 रुपये की गिरावट दर्शाती लिवाल 75,000 रुपये और बिकवाल 76,000 रुपये प्रति सैकड़ पर बंद हुई।

रुपये की गिरावट रोकने के लिए हस्तक्षेप करे सरकार: एसोचैम

नयी दिल्ली। उद्योग संगठन एसोचैम ने आज कहा कि रुपये में और गिरावट नहीं हो यह सुनिश्चित करने के लिए रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय को मिलकर काम करना चाहिए। एसोचैम ने कहा कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और रुपये के मूल्य में और गिरावट से देश को 'आयात से उपजी मुद्रास्फूर्ति' का सामना करना पड़ सकता है। एसोचैम के महासचिव डी . एस . रावत ने कहा, "हमें मालूम है कि रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय को वृहद आर्थिक स्थिरता बनाये रखने के लिए उथल - पुथल के हर मोके पर साथ काम करना चाहिए।" उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक अभी विदेशी मुद्रा विनिमय दरों को बाजार के ऊपर छोड़ दिया है। उसे ईरान परमाणु समझौते पर अमेरिकी रुख , ओपेक देशों द्वारा कच्चा तेल के उत्पादन में पर्याप्त से कम वृद्धि और उभरते वित्तीय बाजारों पर दबाव जैसे भू - राजनीतिक कारकों द्वारा होने वाली अनिश्चितता और उथल - पुथल के समय जरूर हस्तक्षेप करना चाहिए। उन्होंने कहा कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को सहज स्थिति देने के लिए सेबी , रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय को द्वितीयक ऋण व शेयर बाजारों में निवेश के नियमों का सरलीकरण करना चाहिए।

जीएसटी लागू होने के एक वर्ष पूरे होने पर पीएम मोदी ने कहा, विकास और सरलता आयी

नई दिल्ली (एजेंसी)

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने माल एवं सेवाकर (जीएसटी) व्यवस्था के तहत सभी वस्तुओं पर एक ही दर से कर लगाने की अवधारणा को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि मिस्रिडिज कार और दूध पर एक ही दर से कर नहीं लगाया जा सकता। उन्होंने कहा कि जीएसटी के तहत सभी वस्तुओं पर 18 प्रतिशत की एक समान दर से कर लगाने की कांग्रेस पार्टी की मांग को यदि स्वीकार किया जाता है तो इससे

खाद्यान्न और कई जरूरी वस्तुओं पर कर बढ़ जायेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जीएसटी लागू होने के एक साल के भीतर ही अप्रत्यक्ष करदाताओं का आधार 70 प्रतिशत तक बढ़ गया। इसके लागू होने से चेक - पोस्ट समाप्त हो गये , इसमें 17 विभिन्न करों , 23 उपकरों को समाहित कर एक बनाया गया है।

मोदी ने कहा कि जीएसटी समय के साथ बेहतर होने वाली प्रणाली है। इसे लागू करने में गिरावट के लोगों और संबन्ध पक्षों से मिली जानकारी

और अनुभवों के आधार इसमें लगातार सुधार किया गया है। जीएसटी में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , सेवाकर , राज्यों में लगने वाले मूल्यवर्धित कर (वैट) तथा अन्य करों को समाहित किया गया है। इसका उद्देश्य इम्पेक्टर राज को समाप्त करते हुये अप्रत्यक्ष करों को 'सरल' बनाना है। प्रधानमंत्री ने कहा, "यह काफी आसान होता कि जीएसटी में केवल एक ही दर रहती लेकिन इसका यह भी मतलब होगा कि खाद्य वस्तुओं पर कर की दर शून्य नहीं होगी। क्या हम दूध और मिस्रिडिज पर एक ही

दर से कर लगा सकते हैं ?" उन्होंने कहा, " इसलिये कांग्रेस के हमारे मित्र जब यह कहते हैं कि हमारे पास जीएसटी की केवल एक दर होनी चाहिये , उनके कहने का मतलब है कि वह खाद्य पदार्थों और दूसरी उपभोक्ता जित्तों पर 18 प्रतिशत की दर से कर लगाना चाहते हैं। जबकि वर्तमान में इन उत्पादों पर शून्य अथवा पांच प्रतिशत की दर से कर लगाया जा रहा है। " स्वराज पत्रिका की वेबसाइट पर जारी साक्षात्कार में मोदी ने कहा कि आजादी के बाद से जहाँ 66 लाख अप्रत्यक्ष



करदाता ही पंजीकृत थे वहीं एक जुलाई 2017 को जीएसटी लागू होने के बाद इन करदाताओं की संख्या में 48 लाख नये उद्यमियों का पंजीकरण हुआ है।

मारुति की जून में बिक्री 36.3फीसदी बढ़कर 1,44,981 वाहन

नई दिल्ली।

देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया की जून में बिक्री 36.3 फीसदी बढ़कर 1,44,981 कार रही जो जून 2017 में 1,06,394 इकाई थी। कंपनी ने एक बयान में बताया कि उसकी घरेलू बिक्री 45.5 फीसदी बढ़कर 1,35,662 वाहन रही जो पिछले साल जून में 93,263 वाहन थी। छोटी कारों की श्रेणी में ऑटो और वैगन आर समेत कंपनी की कुल बिक्री 15.1 फीसदी बढ़कर 29,381 कार रही जो पिछले साल जून में 25,524 वाहन थी। स्विफ्ट, एस्टिलो, डिजायर और

बलेनो की बिक्री 76.7 फीसदी बढ़कर 71,570 वाहन रही जो पिछले साल जून में 40,496 वाहन थी। कंपनी की सेडान श्रेणी में सियाज की बिक्री 60 फीसदी घटकर 1,579 वाहन रही जो पिछले साल इसी अवधि में 3,950 वाहन थी। यूटिलिटी वाहन श्रेणी में अर्टिगा, एस-क्रॉस, विटारा ब्रेजा की बिक्री 39.2 फीसदी बढ़कर 19,321 वाहन रही है जो पिछले साल समान अवधि में 13,879 वाहन थी। कंपनी की वैन ओमनी और इको की



बिक्री 32.3 फीसदी बढ़कर 12,185 वाहन रही तो पिछले साल इसी दौरान 9,208 वाहन थी। कंपनी का निर्यात समीक्षावधि में 29 फीसदी बढ़कर 9,319 वाहन रहा जो पिछले साल इसी दौरान 13,131 वाहन था।

रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में भारी उछाल, बिना-सब्सिडी वाला भी हुआ 55 रुपए महंगा

नई दिल्ली। सब्सिडी वाला रसोई गैस सिलेंडर 2.71 रुपए महंगा हो गया है जबकि बिना सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत 55.50 रुपए बढ़ दी गई है। एलपीजी की अंतरराष्ट्रीय दरों में तेजी और रुपए में गिरावट इसकी वजह बताई गई है। खुदरा तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसी) ने शनिवार को जारी बयान में कहा कि, दिल्ली में सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत आज मध्य रात्रि से 493.55 रुपए हो जाएगी। तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को पिछले महीने के औसत बेंचमार्क दर और विदेशी मुद्रा विनिमय दर के आधार पर एलपीजी की कीमत में संशोधन करती हैं। बयान में कहा गया है कि बिना सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के बड़े दाम पर जीएसटी की गणना से इसके दाम बढ़े हैं। वैश्विक बाजार में दाम बढ़ने से बिना- सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर का दाम 55.50 रुपए बढ़ जाता है। उच्च वैश्विक दरों के परिणामस्वरूप, दिल्ली में बिना सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत 55.50 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ जाएगी। इंडियन ऑयल ने बयान में कहा कि शेष बचे 52.79 रुपए (55.50-2.71 रुपए) ग्राहकों को क्षतिपूर्ति के रूप में उनके बैंक खाते में स्थानांतरित किए जाएंगे। इस प्रकार, जुलाई 2018 में ग्राहकों के बैंक खातों में सब्सिडी हस्तांतरण बढ़कर 257.74 रुपए प्रति सिलेंडर हो गया है।

किडनी ट्रांसप्लांट के बाद पहली बार दिखे जेटली, बोले- टैक्स कलेक्शन में हुई बढ़ौतरी

बिजनेस डेस्क।

जीएसटी को लागू किए आज एक साल पूरा हो गया है। इस मौके पर केन्द्रीय मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इससे देश में अप्रत्यक्ष करों की जटिलता खत्म हुई है। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद पहली बार किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में बोलते हुए जेटली ने कहा कि जीएसटी के चलते टैक्स कलेक्शन में तो इजाफा हुआ ही है, इसके अलावा जरूरी चीजों पर कम टैक्स से जनता को भी राहत मिली है। उन्होंने कहा कि टैक्स कलेक्शन में इजाफा होने के चलते अब सरकार स्लैब में और कमी करके जनता को राहत दे सकती है। जेटली ने कहा कि अडवांस टैक्स पेमेंट के चलते ग्रॉस इनकम में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि जीएसटी की वजह से भारत संगठित बाजार बना है और यह मोदी सरकार के बड़े फैसलों में से एक है। जेटली ने कहा, पिछले साल जुलाई में हमने देश के सबसे टैक्स जटिल सिस्टम को खत्म कर दिया था। तब 13 मल्टिपल टैक्स और 5 मल्टिपल रिटर्न की व्यवस्था थी। टैक्स पर टैक्स लगा था। हर राज्य के अपने अलग रे टे और उसके अनुसार रिटर्न फाइल करना होता था। देश के संघीय ढांचे को ध्यान में रखते हुए यह टैक्स तैयार किया गया। उन्होंने कहा कि जीएसटी



को लाने से पहले हमने हर राज्य से मशविरा किया। जीएसटी कार्डिनल का गठन भी इस तरह से किया गया है कि देश के सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व उसमें हो। उन्होंने कहा कि यह काफी आसान है। इसके तहत आप सिर्फ एक ही बार टैक्स भरते हैं। एक ही रिटर्न फाइल करते हैं। देशभर में तमाम चेक पोस्ट्स खत्म हो गए हैं और जटिलता खत्म हुई है। हम बिना रेट को बढ़ाए और यहां तक कि घटाने के बाद भी रेवेन्यू में इजाफा करने में सक्षम हुए हैं। अरुण जेटली ने कहा कि जीएसटी आने के चलते पिछली अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था की तुलना में 21 फीसदी का इजाफा हुआ है। टैक्स का कलेक्शन बढ़ा है, इसलिए रेट्स में कमी करने और उनके रेशनलाइज करने की क्षमता में इजाफा हुआ है।

देश में अगले 5 साल में खुलेंगे 85 शॉपिंग मॉल



नई दिल्ली।

रीयल एस्टेट सलाहकार कंपनी एनारॉक के अनुसार ऑनलाइन बाजार को लेकर रुझान बढ़ने के बावजूद आने वाले पांच साल में देशभर में 85 नए मॉल खुलेंगे। एनारॉक रिटेल के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनुज केजरीवाल ने अपनी एक रपट में कहा कि भौतिक खुदरा बाजार के खत्म होने के बारे में बहुत चर्चा हुई है क्योंकि देश में ई - वाणिज्य कारोबार बढ़ रहा है, जबकि तथ्य यह है कि देश में शॉपिंग मॉल का निर्माण बस शुरु भर हुआ है, और इनका कारोबार बरकरार रहेगा। कंपनी की रपट के अनुसार अगले पांच साल में देशभर में करीब 85 मॉल खुलने की उम्मीद है। इनमें से करीब 30 नए मॉल 2020 तक शीर्ष आठ शहरों में ही खुलेंगे। केजरीवाल ने कहा कि मॉल में आपको माल को

लेकर उसे छूने और महसूस करने का अवसर मिलता है जबकि आनलाइन शॉपिंग में ऐसा नहीं है। इसके अलावा माल में खरीदारी के लिए जाना पूरे परिवार के लिए बाहर निकलने का एक अवसर प्रदान करता है और वह भी पूरी वातातुकूलित माहौल में। "देश का मध्यम वर्ग इस अनुभव को पसंद करता है।

आनलाइन खुदरा कारोबार इस अनुभव को पीछे नहीं धकेल सकता है, यह समय कोई जल्द आने वाला नहीं है।" केजरीवाल ने हालांकि यह कहा कि ई-कॉमर्स खरीदारी का मॉल के कारोबार पर प्रभाव इस मामले में जरूर पड़ता है कि आनलाइन में ग्राहकों को काफी छूट दी जाती है। उन्होंने कहा कि फिर भी आनलाइन शॉपिंग और खुदरा बिक्री कारोबार जिसमें मॉल भी शामिल हैं दोनों ही भारत में बने रहेंगे। इनका एक दूसरे पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं होगा।

डाउनलोडिंग स्पीड में जियो ने मारी बाजी, एक बार फिर एयरटेल को पछाड़ा

नई दिल्ली।

भारतीय दूरसंचार प्राधिकरण (ट्राई) की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक जियो ने एयरटेल को डाउनलोड स्पीड के मामले में पछाड़ दिया है। जबकि अपलोड स्पीड के मामले में आइडिया सबसे बेहतर है। एयरटेल की डाउनलोड और अपलोड दोनों ही स्पीड कम रही है। अप्रैल में रिलायंस जियो सबसे तेज डाउनलोड स्पीड देने वाली 4जी दूरसंचार कंपनी रही है। वहीं आइडिया सेल्युलर की अपलोड स्पीड सबसे बेहतर दर्ज की गई है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के माईस्पीड पोर्टल के मुताबिक अप्रैल में जियो की डाउनलोड

स्पीड 19 मेगाबाइट प्रति सेकेंड (एमबीपीएस) रही। यह उसकी प्रतिद्वंद्वी कंपनी भारतीय एयरटेल की 9.3 एमबीपीएस स्पीड से लगभग दोगुनी है। इसके अलावा वोडाफोन और आइडिया की डाउनलोड स्पीड क्रमशः 8.8 एमबीपीएस और 6.5 एमबीपीएस रही हैं। वहीं इस अवधि में आइडिया की अपलोड स्पीड सबसे अधिक यानी 6.3 एमबीपीएस रही। जबकि वोडाफोन की अपलोड स्पीड 5.2 एमबीपीएस, जियो की 4.8 एमबीपीएस और एयरटेल की 3.8 एमबीपीएस रही। कंपनी ने लॉन्चिंग के 24 महीनों से भी कम समय में 20 करोड़ माईस्पीड पोर्टल के मुताबिक अप्रैल में जियो की संख्या

19.6 करोड़ थी। केवल अप्रैल महीने की बात करें तो जियो ने इस महीने कुल 96 लाख यूजर्स जोड़े हैं। बता दें कि रिलायंस जियो को सितंबर 2016 में लॉन्च किया गया था। जिसके बाद से कंपनी तेजी से आगे बढ़ रही है। लॉन्चिंग के कुछ महीनों बाद ही नवंबर 2016 में जियो के कुल यूजर्स की संख्या 5 करोड़ पहुंच गई। फरवरी 2017 में रिलायंस



जियो के यूजर्स की संख्या बढ़कर 10 करोड़ हुई। साल के अंत तक यानी नवंबर 2017 में जियो के यूजर्स की संख्या 15 करोड़ पहुंच गई। वहीं मई 2018 में जियो के यूजर्स की संख्या 20 करोड़ पहुंच गई है।

टाटा स्टील, थीसेनकूप के बीच साझेदारी

मुंबई। टाटा स्टील और थीसेनकूप एजी ने अपने यूरोपीय इस्पात कारोबार में बराबर की साझेदारी से एक संयुक्त उपक्रम कंपनी बनाने के लिए निर्णायक करार पर शनिवार को हस्ताक्षर किए। प्रस्तावित कंपनी को थीसेनकूप टाटा स्टील बीवी नाम दिया जाएगा, जो पूरे यूरोप में उच्च गुणवत्ता के फ्लैट स्टील का अग्रणी उत्पादक कंपनी होगी। टाटा स्टील के अध्यक्ष नरराजन चंद्रशेखरन ने कहा, संयुक्त उपक्रम पूरे यूरोप में स्टील कंपनी का प्रसार करेगा। यह टाटा स्टील के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और हम संयुक्त उपक्रम कंपनी के दीर्घकालीन हित के लिए पूर्ण रूपेण प्रतिबद्ध बने रहेंगे। हमें विश्वास है कि यह कंपनी सभी हितधारकों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। थीसेनकूप एजी के सीईओ हीनरिच हींसिंजर ने कहा, हम यूरोप में उद्योग के संगत और रणनीतिक औचित्य के आधार पर स्टील कारोबार में उच्च स्पर्धा पैदा करेंगे। हम यूरोप के प्रमुख उद्योग में रोजगार सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे और मूल्य श्रंखला को कायम रखेंगे। हालांकि समझौता यूरोपीय संघ समेत कई क्षेत्रों में विलय नियंत्रण की मंजूरी के अधीन है। संयुक्त उपक्रम की प्रक्रिया पूरी होने तक दोनों कंपनियों का संचालन अभी अलग-अलग प्रतिस्पर्धी के तौर पर होगा। संयुक्त उपक्रम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही थीसेनकूप स्टील यूरोप और टाटा स्टील यूरोप में एक कंपनी के रूप में एकीकृत होगी।



13 वर्षीय किशोरी के साथ किया दुष्कर्म, किशोरी हुई गर्भवती

सिंगरामऊ । 13 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले के खिलाफ शुक्रवार को पुलिस ने केस दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू की है। क्रांति समय समाचार के संपादक सुरेश मौर्या, एनजीओ अध्यक्ष सुरेश चंद्र शर्मा सुभाष मौर्य, शिवकुमार शर्मा, राजेश कुमार सोनिया ने थाने पर जाकर मामले पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी तो पुलिसकर्मी किसी प्रकार का जवाब न दे सके। जिसके बाद थानेदार ने तुरंत कार्यवाही करने का आश्वासन देकर वहां पर पीड़िता को बुलवाया

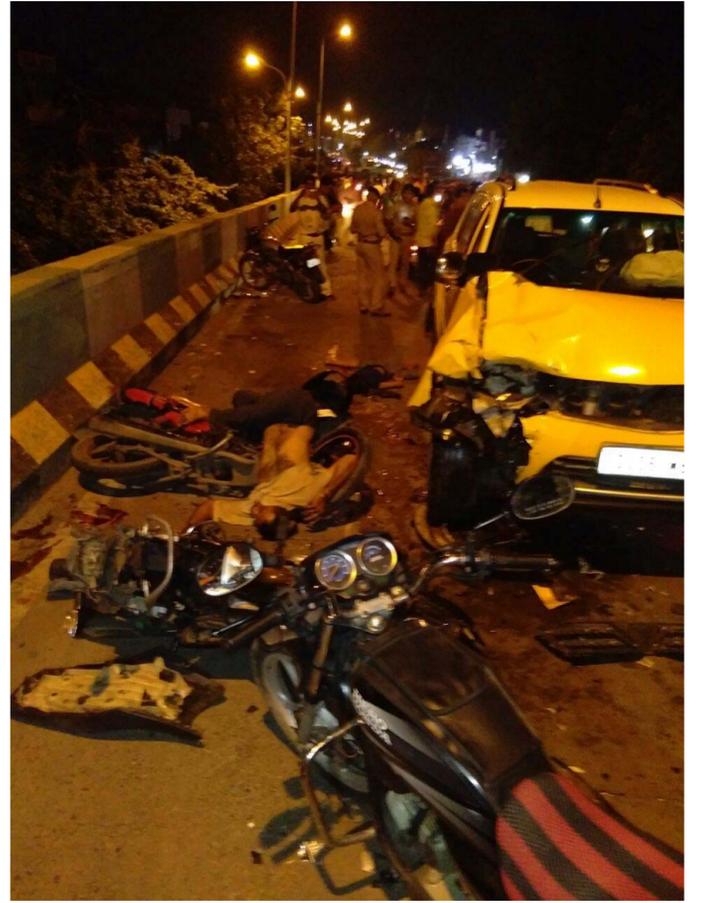
मामा भांजी का रिश्ता हुआ तार-तार



और तुरंत कार्रवाई करने का आला अधिकाधिकारियों के पास से टेलीफोनिक जानकारी देकर

अपनी पढ़ाई कर रही थी। आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले युवक ने किशोरी को बहला फुसलाकर उसके साथ दुर्गम किया जिससे किशोरी गर्भवती हो गई। किशोरी के मामा ने पुलिस को दी गई तहरीर में कहा है कि वह रोज रोजी रोटी के सिलसिले में बाहर रहता है। पड़ोस के युवक ने उसकी भांजी को बहला फुसलाकर 28 अक्टूबर 2017 को उसके साथ दुर्गम किया। जिससे वह गर्भवती हो गई। नौ मार्च 2018 को आरोपी उसे बदलापुर ले गया जहां किसी अस्पताल में

उसका गर्भपात करवा दिया। घर आने पर उन्हें घटना की जानकारी हुई तो थाने आकर तहरीर दी। पुलिस ने शुक्रवार की देर शाम को आरोपी संदीप मौर्य के खिलाफ दुष्कर्म और पाकसों एकट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। संदीप मौर्य इस समय सूत में रह रहा है। जैसे आपको बता दे कि कितने ही आरोपी पुलिस से बचने के लिए बड़े शहरों में रहकर अपना जीवन व्यती करते हैं। जिसे पुलिस आसानी से खोजन नहीं पाती है। और पीड़ित को न्याय नहीं मिल पाता है।



सूत। डिंडोली ब्रिज पर कार और बाईक में भिड़ंत होने से तीन लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कार वाला शराब के नशे में था और वह किसी गाड़ी को ओवर टेकर कर रहा था जिस कारण वह सामने आ रही बाईक से जा टकराया और यह भयान हादसा हो गया।

विवाद पर खुद पुलिस कमिश्नर मीडिया के सामने आये

पीड़िता और आरोपियों के बयान में सख्त विरोधाभास

हमारी भूमिका और जिम्मेदारी पूरे केस में सच्चाई को बाहर लाने की है पीड़िता का विश्वास प्राप्त करेंगे : सीपी

अहमदाबाद। सेटेलाइट गैंगरेप में पीड़िता ने क्राइमब्रांच के जेसीपी जेके. भट्ट पर गंभीर आरोप लगाने पर राज्यभर में खलबली मच गई जिसकी वजह से खुद शहर पुलिस कमिश्नर एके. सिंध को तुरंत मीडिया के सामने आना पड़ा। पुलिस कमिश्नर खुद क्राइमब्रांच पहुंचे थे और पूरे मामले की जानकारी ली। इसके बाद पुलिस कमिश्नर एके. सिंध अरजन्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पुलिस की भूमिका के विरुद्ध उठे सवाल को लेकर बचाव की मुद्रा में देखने को मिला। पुलिस कमिश्नर ने बताया है कि, पीड़िता की एफआईआर, इसके अतिरिक्त बयान और आरोपियों के बयान में बहुत विरोधाभास है, इसकी वजह से फोरेन्सिक एक्जामिनेशन की मदद से इसके समाधान का प्रयास हम कर रहे हैं। पीड़िता को पुलिस के प्रति अविश्वास बढ़ गया है यह विश्वास प्राप्त करने के लिए हम प्रयास करेंगे। हमारी भूमिका और जिम्मेदारी पूरे केस में इसकी प्रामाणिकता लाना जरूरी है। पुलिस कमिश्नर एके. सिंध ने आगे बताया है कि, पीड़िता की शिकायत में तीन आरोपी के नाम हैं। जिसमें से दो आरोपियों को पुलिस ने दूढ़ निकाला है।

पीड़िता के जेके. भट्ट पर आरोपों से खलबली

दुष्कर्म के बदले में धोखाधड़ी की शिकायत के लिए दबाव

अहमदाबाद। शहर के घोडासर क्षेत्र में रहती युवती का नेहरूनगर सर्कल से ज़ांसी की रानी के पुतला के सर्विस रोड पर स्कॉर्पियो कार में आये शख्नों ने अपहरण करके उसके साथ चालू कार में ही बारबार बलात्कार करने के केस में शिकार होनेवाली पीड़िता ने रविवार को क्राइमब्रांच के जेसीपी जेके. भट्ट पर खराब व्यवहार और शिकायत बदलने के गंभीर आरोप लगाने पर भारी खलबली मच गई है। पीड़िता ने प्रेस के समक्ष रोते-रोते जेके. भट्ट इतने हद तक खराब व्यवहार की बात जेके. भट्ट का खराब व्यवहार का सवाल और मानसिक टोचर से मुझे आत्महत्या करने का मन हुआ था। जेके. भट्ट ने मेरे साथ क्रिमिनल जैसा व्यवहार किया है। उन्होंने कहा था कि, जिस घटना को आप दुष्कर्म कहती

है इसमें लकड़ी जैसी वस्तु का उपयोग किया गया था इसे रेप नहीं कहा जा सकता है। रेप किसे कहते हैं यह हम निश्चित करेंगे। उच्च पुलिस अधिकारी जेके. भट्ट ने मुख्य आरोपी वृषभ मारू को बचाने का प्रयास किया गया था और मुझे धमकी दी थी कि, आप अभी भी विचार कर लो आप दुष्कर्म के बदले में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करा दे। पुलिस ने मेरा बयान मेजिस्ट्रेट के समक्ष नहीं लिया है। अहमदाबाद शहर सहित राज्यभर में भारी सनसनी मचाने वाले दुष्कर्म केस में शिकार होनेवाली पीड़िता ने रविवार को मीडिया के समक्ष उपस्थित होकर अपनी पीड़ा को व्यक्त करते हुए कहा कि, मुझे गत दिन क्राइमब्रांच की ऑफिस में बुलायी गई थी, जहां मेरे साथ उच्च पुलिस अधिकारी जेके.

भट्ट द्वारा बहुत ही खराब व्यवहार किया गया। जेके. भट्ट ने मुझे गंदे तरीके से सवाल किया था। उन्होंने सवाल पूछा था कि आपको किसलिए वहां जाने की जरूरत थी मुझे बयान बदलने के लिए दबाव बनाया गया और शिकायत बदलने के लिए कहा गया। मुख्य आरोपी वृषभ को वह बचा रहे थे। उन्होंने कहा कि वृषभ तो गाय जैसा है। यह ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। दुष्कर्म के स्थान पर चीटींग की शिकायत लिखाने के लिए कहा गया था। मुझे क्रिमिनल के तौर पर ट्रीट किया गया और बारबार पुलिस स्टेशन बुलाया गया। जेके. भट्ट के खराब व्यवहार और पूछताछ के बाद मुझे आत्महत्या करने का विचार आया था। पीड़िता ने आगे बताया है कि, जेके. भट्ट जैसे अधिकारी की वजह से पीड़ित युवती सामने

नहीं आती है। अपराधियों को बचाने का प्रयास हो रहा है। यह केस की निष्पक्ष तरीके से महिला अधिकारी द्वारा जांच हो। यह पुलिस जांच से संतुष्ट नहीं है और पुलिस द्वारा अपराधियों को बचाव किया जा रहा है। पुलिस इसे बयान बदलने के लिए दबाव बना रही है। हाईकोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार शिकायत के 24 घंटे में ही पीड़िता का बयान महिला मेजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होता है। जो चार दिन बाद भी नहीं हुआ है। मुझे न्याय चाहिए और मुझे न्यायंत्र पर विश्वास है। दूसरी तरफ पीड़िता के आरोप बाद बाल और महिला कल्याण मंत्री विभावरीबहन दवे ने बताया है कि, महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और आरोपियों को छोड़ा नहीं जाएगा।

महिलाएं सुरक्षित होने के दावे गलत निकले अहमदाबाद में रेप की सबसे अधिक घटनाएं हुई: रिपोर्ट

अहमदाबाद। अहमदाबाद में निर्भयाकांड की सामुहिक गैंगरेप की घटना के सालो बाद भी इस प्रकार की घटनाओं का सीलसीला जारी रहा है। बलात्कार की घटनाओं के मामले में अहमदाबाद टोप पर है। दुसरी ओर इस मामले में गुजरात में राजकीय गर्मी भी बढ़ गई है। गुजरात में महिलाएं

स्वतंत्र रूप से कोई परेशानी बिना कोई भी इलाके में घुम सकती है इस तरह के दावे बीजपी की ओर से किये जा रहे थे किन्तु अब अहमदाबाद समेत राज्य में रेप के केस में तेजी से बढ़ती दर्ज हुई है। महिलाएं सुरक्षित होने के दावे गलत साबित हो रहे हैं। आंकड़ों पर नजर की जाए तो पिछले दो

साल में गुजरात में बलात्कार की 1117 घटनाएं दर्ज की जा चुकी हैं। राज्य के गृह विभाग की ओर से जो आंकड़े दिये गए हैं उनमें बताया गया है कि मेट्रोसिटी अहमदाबाद में क्राइम रेट में बढ़ती दर्ज हुई है। पिछले दो सालों में अहमदाबाद में रेप के 149 केस और अहमदाबाद ग्राम्य को

मिलाकर कुल 291 केस दर्ज किये गए हैं। अहमदाबाद के लिए यह शरमजनक घटना है। सूत शहर और जिले में 249, बडौदा में 66, राजकोट शहर और जिले में 100 केस दर्ज किये जा चुके हैं। चौकाने वाली बात यह है कि गुजरात का कोई जिला ऐसा नहीं है जहां रेप की घटना नहीं बनी है।



जीएसटी व्यवस्था लागू होने के एक वर्ष पूरा होने के अवसर पर गुजरात के उपमुख्यमंत्री नीतिन पटेल इस संदर्भ में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित हुए। एएमए में कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

साल 2017 में अबतक 143 की मौत

डायमंड शहर सूत में रोड एक्सिडेंट में मौत अधिक

सूत। गुजरात के सूत शहर में साल 2017 में इसी समय के दौरान 106 रोड एक्सिडेंट की तुलना में इस साल के प्रथम छह महीने में रोड एक्सिडेंट में बढ़ती दर्ज हुई है। सूत के रास्ते पर मृत्यु में 26 फीसदी की बढ़ती दर्ज हो चुकी है। साल 2017 में 106 मौत की तुलना में साल

2017 के प्रथम छह महीने में 143 मौत रोड एक्सिडेंट में हो चुकी है। आंकड़ें दर्शाते हैं कि सूत के रास्ते किलर बन चुके हैं। डायमंड सिटी के किलर बन चुके रास्ते पर दुर्घटनाओं में मृतकों की संख्या बढ़ रही है। पुलिस जांच में जानने को मिला है कि सबसे अधिक टू व्हीलर ड्राइवर्स

की मौत हुई है। साइकल सवार मौत की संख्या चार दर्शाई गई है। पैदल जा रहे लोगों से टक्कर में 61 लोगों की मौत हुई है। कारचालक, रिक्साचालक की मौत की संख्या कम है। साल 2017 में सूत शहर में 249 रोड एक्सिडेंट ऐसे थे जिस में लोगों की मौत हुई थी। दुसरी ओर इस साल के पिछले

छह महीने के दौरान इस प्रकार की मौत की संख्या 139 बताई गई है। पुलिस के रिकॉर्ड में बताया गया है कि मृतकों में सबसे अधिक मौत 10 से 25 साल के आयु के लोगों की हुई है। जिसमें पुरुषों की संख्या सबसे अधिक दर्शाई गई है। 45 से 60 साल के पुरुषों के मौत की संख्या 20 बताई गई है।

महादेव मीडिया

रोहताश यादव 9924144499, 7015339195

वीजिटिंग कार्ड, बिल बुक, लेटर पैड, बेनर, पोस्टर, आदि का डिजाइन बनवाने के लिए संपर्क करें। (हिन्दी, गुजराती)



हिन्दी, गुजराती न्युज पेपर डिजाइन करवाने के लिए संपर्क करें।

304 केवल कॉम्प्लेक्स नवा गाम, डिंडोली, उधना सूत।